

विचार मंथन

 @Pratahkiran
 www.pratahkiran.com
पटना, बुधवार, 08 नवम्बर, 2023

सड़कों पर जारी मौतें

साल 2022 में भारत में सड़क हादसों में एक लाख 68 हजार लोग

तल का तलब व पाश्यन एशिया का संकट

सात अक्षर

हमले और करीब 200 यहूदियों को बंधक बना लिया जाने के बाद से इजराइल फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है। दोनों ही तरफ के हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान हिंसा का शिकाया होने वालों का होता है, चाहे वे सैनिक हों या नागरिक। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई पश्चिमी देशों ने इजराइल के साथ एक-जुटा प्रदर्शन की है। यहां तक कि हमास के हमले के कुछ ही घंटों बाद, भारत ने उसका समर्थन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर के बारे में धूंध खोलने में कई महीने लगा दिए, लेकिन इजराइल के साथ हमदर्दी जताने में उन्होंने जरा भी देरी नहीं की। पूरे मामले में अपराधी बताया जाने वाला हमास (इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन) स- 1987 में गठित फिलिस्तीनियों की एक सशर्श संस्था और मुख्य पार्टी है। इसके सशस्त्र विभाग का गठन 1992 में हुआ था। इस मामले में कई स्तंभकार के बल हमास को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं और युद्ध को स्थितियां निर्मित करने के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन साथ ही यह भी स्वागतयोग्य है कि इंग्लैंड और अमेरिका में इजराइल के खिलाफ कई बड़े प्रदर्शन हुए हैं, हालांकि मीडिया ने उनकी बहुत कम चर्चा की है।

में लिखा था, 'फालस्तीन उसा तरह से अबल लागा का है, जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। उठने वह भी लिखा कि इसाइयों के हाथों यहूदियों ने प्रताड़ा भोगी है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें मुआवजा देने के लिए फिलिस्तीनियों से उनकी जमीन छीन ली जाए। यहूदी यूरोप में व्याप यहूदी-विरोधवाद के शिकार रहे हैं। यहूदियों के प्रति इसाइयों के बैरभाव के कई कारणों में से एक यह है कि ऐसा माना जाता है कि इसा मसीह को मूली पर चढ़ाये जाने के लिए यहूदी जिम्मेदार थे। आगे चलकर व्यापारिक होड़ के कारण यह बैर और बढ़ा। यहूदी-विरोधवाद का सबसे क्रूर और सबसे दिंसक पैरोकार था एडोल्फ हिटलर, जिसने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था। अकेले गैस चैम्बरों में 60 लाख यहूदी मरे गए थे। यूरोप में यहूदियों को कई तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इसी के नतीजे में जोयनिम्य या यहूदीवाद का जन्म हुआ। यथोंडेर हट्टर्सजल ने दि ज्यूझ रस्टे शीर्षक से एक युस्तक लिखी और इस मुद्रे पर स्विट्जरलैंड में कुछ यहूदियों को बैठक हुई। ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले से उठने वाले धोषणा की कि फिलिस्तीनी की भूमि यहूदियों की है। उनका नारा था, भूमि विहीन मानवों (यहूदियों) के लिए मानव-विहीन भूमि (फिलिस्तीन)। जाहिर है, यह नारा उस भूमि पर 1000 साल से रह रहे उन फिलिस्तीनियों के साथ बेरहमी करने का आहान था जो केवल मुसलमान नहीं थे। उनमें से 86 फीसदी मुसलमान, 10 फीसदी ईसाई और 4 फीसदी यहूदी थे। बरहान एक ज्यूझ नेशनल फण्ड स्थापित किया गया और दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन आकर वहां जमीन खरीदने लगे। शुरूआत में अधिकांश यहूदी भी यहूदीवाद के खिलाफ थे। जो यहूदी फिलिस्तीन में बसे, उनसे कहा गया कि वे अपनी जमीन न तो किसी अरब को कियाये पर दें और न किसी अरब को बेचें। उनका इरादा साफ था- धीरे-धीरे फिलिस्तीन पर कब्जा जमाते जाओ। यहूदियों की संख्या बढ़ती गयी, फिर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत फिलिस्तीन का शासन इंग्लैंड के हाथ में आ गया और वहां की आतंरिक समस्याएं बढ़े लगी। सन 1917 में इंग्लैंड ने ह्यूबेलफोर घोषणापत्र जारी कर फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए गृहरास्ट्र की स्थापना का समर्थन किया। इस तरह फिलिस्तीनी की समस्या की जड़ में ब्रिटिश उपनिवेशवाद है। यहूदी लेखक अर्थर केरसोर ने ह्यूबेलफोर घोषणापत्र के बारे में लिखा, इससे विचित्र दस्तावेज दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। अमरीकी-इजराइली इतिहासवेता मार्टिन क्रेमर के अनुसार, ह्यूब दस्तावेज संकीर्ण और तरह-तरह के प्रतिबंधों पर आधारित राजनीतिक यहूदीवाद की ओर पहला कदम था। अब लोगों ने 1936 के बाद से इस घुसपैठ का प्रतिरोध करना शुरू किया, परन्तु उसे बिटेन ने कुचल दिया। हिटलर द्वारा यहूदियों की प्रताड़ा के चलते द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद यहूदी और बड़ी संख्या में यहां बसने लगे। यह दिलवस्या है कि यूरोप के देशों और अमरीका ने यहूदियों को उनके देश में बसने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं किया। कल वक्त बाद फिलिस्तीन को दो

हिस्सों में बांट दिया गया- फिलिस्तीन और इजराइल, और यह तय हुआ कि यौक्षण्यम् अपै ब्रेक्वेंडम् को अंतर्राष्ट्रीय विभाजना में शामिल किया जाएगा।

असुरक्षित हो गई बेटियां कब लकड़ेगे अत्याचार?

आज काई गी विश्वास के योग्य नहीं रहा है किस पर विश्वास करें अपने ही हैवान बन रहे हैं। आज बाबुल की गलियाँ ही नरक बन गई हैं। अपने इथक ही भक्त बन गए हैं बह-बेटिया घर में ही असुखित हैं समय पर ऐसे सिनाने कर्म होते हैं कि कायानात कांप उठती है कि आटमी इतने नीच काम क्यों कर रहा है। महिलाएं कहीं भी महफूज नहीं हैं। महिलाओं पर बढ़ते अत्याधार लकड़े का नाम नहीं ले रहे हैं देख में प्रतिदिन घिटत हो रही बारातों से महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लगता जा रहा है कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। इन बारातों से हर भारतीय उद्देशित है। सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुरुषा इतनाम करने होंगे तभी इन पर सोक लग सकती है। जगन्नाथ दिल ढहला देने वाली दुष्कर्म की घटनाओं से जनमानस खोफजाता है। अधिक बढ़ता तक बेटियां दरिद्री का शिकाइ होती रहेंगी। ऐसी बारातों बहुत ही पिंडीय हैं। बेल्यूफ दरिंतें अराजकता फैला रहे हैं दरिंदों की दरिद्री की बारातों कब लकड़ी, अपाराध की तरीख बदल जाती है, मगर तस्वीर नहीं बदलती। बेशक प्रतिवर्ष ४ मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया गया। मगर ऐसे आयोजन केवल मात्र औपचारिकता भर रहे हैं क्योंकि हर वर्ष एक संकल्प लिया जाता है कि महिलाओं को अत्याधारों से मुक्ति दिलाई जाएगी अत्याधारों का खाला किया जाएगा सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं



नरेन्द्र भारती लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

क्षेत्र रहेगी। ऐसी बारिदातें बहुत ही चिंतनीय

हैं। बेखौफ दरिंदे अराजकता फैला रहे हैं दरिंदों की दरिंदगी की बारबातें कब रुकेगी, अपराध की तारीख बदल जाती है, मगर तस्वीर नहीं बदलती। बेशक प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया गया। मगर ऐसे आयोजन केवल मात्र औपचारिकता भर रह गए हैं क्योंकि हर वर्ष एक संकल्प लिया जाता है कि महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जाएगी अत्याचारों का खात्मा किया जाएगा सुरक्षा के लिए बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं मगर धरातल की सच्चाईयां बेहद ही खौफनक तस्वीरें प्रस्तुत कर रही हैं। आधी दुनिया पर बढ़ते अत्याचार देश के लिए अशुभ संकेत हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता की बुलिदियां छुट्ट रही हैं चांद तक अपनी काबिलियत का परचम लहरा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सैंकड़ों कड़े कानून बनाए गए हैं मगर यह कानून सरकारी फाईलों की धूल चाट रहे हैं अगर सही तरीके से लागू किए होते तो इन मामलों में इंजाफा नहीं होता। आज महिलाएं कहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं चाहे घर हो दफतर हो, बस, सड़क, गली या चैराहा हो महिलाएं हर जगह असुरक्षित ही महसूस कर रही हैं। 1. 2019, 2020, 2021, 2022 में भी दरिंदों ने दरिंदगी जारी रखी 'वर्ष 2023 में भी हालात सुधर नहीं रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 12 सितंबर 2018 को हरियाणा के रोड़ाड़ी में एक 19 साल की मेधावी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म कर दिया था। 27 जून 2018 को मध्यप्रदेश के मंदसौर

बच्ची से सामूहिक दुर्घटक की जघन्य घटना से हर भारतीय उद्वेलित हुआ था। यह बच्ची तीसरी में पढ़ती थी। मासूम से हुई रदिंगी व हैवानियत की यह घटना बहुत ही दिल दहलाने वाली थी। दरिंदों ने जिस बर्बरता व हैवानियत से घटना को अंजाम दिया था उससे रॉगेट खड़े हो जाते हैं। दरिंदों ने दरिंदी की हड़े पार कर दी थी। 16 दिसंबर 2012 सामूहिक दुर्घटक करने वाले दुर्घटक की वारदात से हर भारतीय उद्वेलित हुआ था। यह रॉगेट खड़े कर देने वाली घटना बहुत ही दुखद ही। हर रोज अस्मत लूटी जा रही है। दरिंदों द्वारा हर राज्य में दरिंदी का सामाज्य बना रहे हैं। दरिंदों की अराजकता बढ़ती ही जा रही है। जंगलराज स्थितियां बन रही हैं। कानून को धंत बताकर दरिंदे दरिंदी का तांडव कर रहे हैं। दरिंदों को सरे आप मौत के घाट उतारना हांगा ताकि आने वाले समय में दरिंदे कई बार सोचेंगे की उनकी करतूतों का क्या अंजाम होगा। अब समय आ गया है कि दरिंदों को फांसी की सजा से ही इन मामलों पर विराम लग सकता है। वर्ष 2023 के जनवरी माह से देश के हर राज्य में इन मामलों में बेतहासा बृद्धि होती जा रही है। साल के दस माह में यह दुर्घटक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार को इन मामलों पर त्वरित कारवाई करनी होगी। हर रोज दरिंदे दरिंदी का तमाशा कर रहे हैं। देश में दुर्घटक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इससे पहले कठुआ में भी एक बच्ची के साथ दरिंदी का मामला प्रकाश में आया

वर्ष 2019 में एक खौफनाक व दरिद्रगी की हड़े पर करने वाला घटनाक्रम पंजाब के मोगा में हुआ था जब बदमाशों ने चलती बस में लड़की से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर बस सं फैंक दिया जिस कारण उस लड़की की मौत हो गई थी। गत वर्ष उत्तर प्रदेश का बंदायू एक बार फिर शर्मसार हुआ था जहां एक बार फिर दो नाबालिंग चचेरी बहनों से गैरेरेप का मामला प्रकाश में आया था पांच आरोपियों ने शौच को गई नाबालिंगों को अगवा करके उनके साथ बटूक की नोक पर दुष्कर्म किया था। आज बाल-विवाह हो रहे हैं नाबालिंग लड़कियों की शादियां अधेंडो से की जा रही हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध समाज को कारवाई करनी चाहिए। 16 दिसंबर 2012 को जो हादसा दिल्ली में निर्भया के साथ हुआ था उसके बाद देश में महिलाओं से होने वाले दुष्कर्मों की बाढ़ सी आ गई कि हर दिन राजधानी से लेकर शहर व गांवों में सामूहिक दुष्कर्म थर्मने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज हर जगह दुश्यसन महिलाओं की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। विश्व गुरु कहलाने वाले भारत में महिलाओं पर जुल्मों की सूची लम्ही होती जा रही है। जब देश की राष्ट्रीय राजधानी ही सुरक्षित नहीं है तो महानगरों व छोटे कस्बों का ब्याहाल होगा इससे अदांजा लगाया जा सकता है देश में आज भूल हत्याएं हो रही हैं नवजात शिशु झाड़ियों व कूड़ेदानों व मर्दियों में मिल रहे हैं जिनमें ज्यादातर शिशु लड़कियां ही होती हैं। आज लड़कियों से इतनी नफरत क्यों रहा है कि जिसने उसे जन्म दिया वह भी एक लड़की ही थी। देश में ऐसे मामले प्रतिदिन घटित हो रहे हैं। नवजात व अबोध बच्चियों से दुष्कर्म हो रहे हैं। गत वर्ष दिल्ली में गुड़िया के साथ ऐसा ही एक दरिद्री हुई थी जब एक किराएदार ने उसके साथ रुप कंप देने वाला धिनौना काम किया था। दरिद्र हर जगह दरिद्री की शरणस्थली बन रहे हैं। कुछ बीमार मानसिकता के लोगों ने भारत की छवि को दागदार किया है जनमानस को अब संकल्प लेना होगा तथा एक जुट होकर ऐसे लोगों का खात्मा करना होगा जो देश के लिए कंलक हैं। फांसी के जितने भी मामले लंबित हैं त्वरित कारवाई करके दरिद्रों का सर्वनाश करना चाहिए। ताकि अनेक वाले समय में ऐसे अमानवीय कृत्यों पर लगाम लग सकें। यदि अब भी कानूनों में सख्ती न बढ़ती तो ऐसे दरिद्रों फिर से इन धिनौनी वारदातों को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए अब ऐसे लोगों के समाज से बहिष्कृत करना चाहिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि देश के सावजनिक स्थलों पर हर समय सुरक्षा व्यवस्था कायम की जाए। साथी वर्दी में महिला पुलिस तैनात करनी चाहिए सरकार को बिना समय गंवाए हुए दरिद्रों का खात्मा करना चाहिए। ऐसे दरिद्रों देश के लिए घातक होते हैं ऐसे दरिद्रों न जाने कैसे वातावरण में रहते होंगे ऐसे लोगों को समाज की कोई फ़िक्र नहीं होती कि उनके कृत्यों से पूरा समाज द्रवित होता है। समाज में ऐसे लोग बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे हैं ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए

सावधान का धार्जया राजनातं न धर्म का प्रवर्श शाष स्तर स....?

भा भारत क मंदिरोंआ का धामभरु हा समझा रह ह आ और धामक अवतारो का वतरणा थामकर अपना चुनाव नया पार लगाना चाहते है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने इसी गरज से मध्यप्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान भगवान राम को आदिवासियों से जोड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास किया। उन्होंने आदिवासियों को कहकर महिमा मंडन किया कि भगवान राम को पुरुषोत्तम बनाने वाले आदिवासी ही थे, उन्होंने मध्यप्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में गौड़, बैगा, पनिका जैसा आदिवासी गोटर बहुसंख्यक मात्रा में है और ये वर्ग क्षेत्र की 47 सीटों को प्रभावित करते है, इसलिए मोदी ने यहां यह राजनीतिक खेल खेला। ये सीटें प्रारंभ से ही कांग्रेस प्रभावित रही है, इसलिए यहां राजनीति जरुरी समझी गई। यद्यपि भारतीय सविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का सहारा लेना गैरकानूनी है, किंतु यदि राजनीति के शीर्ष पुरुष ही सविधान की परवाह न करें तो उसे क्या कहा जाए? यह तो सिर्फ मध्यप्रदेश के महाकौशल क्षेत्र की ही गत हुई, किंतु इससे भी बढ़कर पांच राज्यों के विधानसभाओं और करीब 150 दिन बाद होने वाले लोकसभा चुनावों के पूर्व अभी से अयोध्या के प्रस्तावित भव्य राम मंदिर को राजनीतिक स्वार्थ के तहत मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है



आमप्रकाश महता
विख्यात अर्थशास्त्री

या आजादी के पचहत्तर साल बात
भी देश के नामचीन राजनीतिक दल
मतदाताओं का मनोविज्ञान समझ
नहीं पाए है और इसलिए आज भी
उसी पुराने ढर्डे से चुनाव जीत हासिल
करना चाहते हैं? आज यह सवाल
इसलिए सहज रूप से सामने आ
रहा है, क्योंकि राजनीतिक दल और
उसके सर्वगुण सम्पन्न नेता अभी भी
भारत के मतदाताओं को धर्मभिरु ही
समझ रहे हैं और धार्मिक अवतारे
की वैतरणी थामकर अपनी चुनावी
नेता पार लगाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री
नरेन्द्र भाई मोदी ने इसी गरज से
मध्यप्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरा-
भगवान राम को आदिवासियों से
जोड़कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने का

प्रयास किया। उन्होंने आदिवासियों को कहकर महिमा मंडन किया कि भगवान् राम को पुरुषोत्तम बनाने वाले आदिवासी ही थे, उन्होंने मध्यप्रदेश के महाकैशल क्षेत्र में गौड़, बैगा, पनिका जैसा आदिवासी बोटर बहुसंख्यक मात्रा में है और ये वर्ग क्षेत्र की 47 सीटों को प्रभावित करते हैं, इसलिए मोदी ने यहां यह राजनीतिक खेल खेला। ये सीटें प्रारंभ से ही कांग्रेस प्रभावित रही हैं, इसलिए यहां राजनीति जरूरी समझी गई।

ही संविधान की परवाह न करें तो उसे क्या कहा जाए? यह तो सिर्फ मध्यप्रदेश के महाकौशल क्षेत्र की ही बात हुई, किंतु इससे भी बढ़कर पांच राज्यों के विधानसभाओं और करीब 150 दिन बाद होने वाले लोकसभा चुनावों के पूर्व अभी से अयोध्या के प्रस्तावित भव्य राम मंदिर को राजनीतिक स्वार्थ के तहत मुख्य मुद्दा बनाने की तैयारी की जा रही है, जिससे कि हिन्दू वोट प्रभावित हो सकें। लोकसभा चुनावों के चंद्र दिन पहले 22 जनवरी को अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की जानी है और मूर्ति स्थापना से पूर्व रामलला की दस करोड़ तस्वीरों के घर-घर बढ़ाइ जाने

मन्चन शुरू करेगे।
 इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि विधानसभाओं और भावी लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा के प्रचार का मुख्य मुद्दा धर्म आधारित होगा तो कतई गलत नहीं होगा। इसी परिवृष्टि को देखकर देश के जगरूक और बुद्धिजीवी मतदाताओं के दिल-दिमाग में यह सबल उठना स्वाभाविक है कि क्या शीर्ष राजनेता अभी भी देश के आम मतदाताओं को सतर तक पुराना अनजान और अशिक्षित मतदाता ही मानते हैं, जो धर्म के आधार पर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं और अपनी कुर्सी को हाथीर्घीवील बनाना चाहते हैं। जबकि आज के राजनेता वास्तव में भरोसे के संकट और वादों की ग्यारंटी के बीच की दूरी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि जागरूक और बुद्धिजीवी मतदाता भरोसे पर भरोसा नहीं करते, उन्हें तो ठोस तथ्यों के साथ बादे पूरे होने की ग्यारंटी चाहिए, जिसका आज सर्वत्र अभाव है। इसलिए आज की सबसे पहली जरूरत राजनेताओं द्वारा अपने सविधान पर भरोसा करने और उसके ईमानदारी पूर्ण परिपालन करने की है, न कि उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बनाने की, आखिर देश की राजनीति व उसके नेता देश और देशवासियों के बारे में कब चिंतन मनन करें? या ऐसा वक्त अब आने वाला नहीं है?

आटा ले लो आटा , मोटी बांड सहता आटा

गानेश अतल

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने सस्ता आटा, सस्ती दाल लाच कर एक नेक काम किया है। सरकार की ये जनकल्याणकारी योजना है कि योगोक्ति देश में अब एक तरफ अडानी का फार्क्चून आटा आम जनता का खून पी रहा है तो दूसरी तरफ अडानी दाल। ऐसे में अडानी के कान खींचने के बजाय सरकार ने अपनी ही देशी सहकारी संस्थाओं को अडानी के मुकाबले मैदान में उतार दिया या यूं कहिये खुद मैदान में मोर्चा सम्हाल लिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस भारत और की ब्रांडिंग करने की उदारता दिखाई है। केंद्र सरकार देशभर में 27.50 रुपए प्रति किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्ध करागायी। केंद्रीय मंत्री पीयर गोगल रवाना किया। इस 10 किग्रा और 30 किग्रा के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। मोदी जी देश के पहले उदार प्रधानमंत्री हैं जो चीनी पेटीएम से लेकर देशी भारत आटा बेचने तक के लिए अपनी तस्वीर के इस्तेमाल की इजाजत देते हैं। वे पांच किलो मुफ्त अन्न का थैला हो या कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए टीके का प्रमाणपत्र सभी जगह छपने के लिए राजी हो जाते हैं। इतना सहज, सरल और उदार प्रधानमंत्री कम से कम मैंने तो अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा। इस समय सचमुच जनता महगाई की मार से सिसकर रही है। अर्तान्न दहर कर ही है। बाजार पर अडानी और अम्बानी जी का काढ़ा है। वे दोनों महावृत्त आटा-दाल से लेकर हर माल पर हावी हैं। औपें दूनकी जारी मरकूप के गाम सस्ता भारत आटा और अरहर की दाल बेचने का समानांतर इत्तजाम कर सचमुच लोकल्याणकारी काम किया है। सरकार देश की 80 करोड़ आबादी को पहले से मुफ्त का राशन दे रही है। अब जो शेष 60 करोड़ लोग बचे वे मोदी ब्रांड सस्ता भारत आटा और दाल खरीदकर अपना जीवनयापन आसानी से कर सकते हैं। अपने अपको सच्चा भारतीय साबित करने के लिए सस्ता भारत आटा खाने से सस्ता दूसरा क्या रास्ता हो सकता है? अपाको मैं इस बोजना के बारे में तपसील से बताये देता हूँ। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक देशभर में कोई 2 हजार ठिकानों पर यांत्रिक ब्रांड सस्ता आटा मिलेगा। इसे नेशनल एप्रिकल्चरल को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन अफ इंडिया एम्पिरेट द्वारा मार्केट के माथ ले देणेवाले भी आटा को ऑसात कीमत 35 से 50 रुपए किलो है। गेहूँ की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है। हमारी सरकार मैंगाई 21 राज्यों के 55 शहरों में 329 खुदराएँ भंडारों कि माध्यम से घटी ड्रोन पर प्याज बेच रही है। केंद्रीय भंडार ने भी बींबते बाजार में बनिया बनकर उत्तर आती है। ये दुस्रोंहस का काम है अन्यथा सरकार का काम प्रशासन करना होता है न कि दाल-आटा बेचना। पिछले दिनों जब पहले हम लोग पूरे साल के लिए गेहूँ खरीदकर रखते थे और फिर चक्की पर जाकर गेहूँ पिसावा लाते थे। अब न गेहूँ खरीदकर भंडारण की क्षमता बची है और न चक्की तक जाने का हासला, सो मजबूत अडानी, अम्बानी आशीर्वाद आसान काम है। हमारी सरकार हमेशा आसान काम को प्राथमिकता देती है। प्याज की बढ़ी कीमतों से उपभोक्ताओं की राहत देने के लिए सरकार 25 किलो की दाम में प्याज बेचनी शुरू की है। नेशनल का नितना सामान लेने वालाकृष्ण शर्मिनी

सुबह-सुबह वोट डालने पहुंचे सीएम जोरमथांग, बैरंग लौटना पड़ा



डालूंगा।

सरकार बनाने का विश्वासः मुख्यमंत्री और मिजानेशनल फंट के चीफ जारमथांग ने कहा कि उन्हें पूरा विकास है कि उनकी पार्टी बहुप्रत के सरकार बना लेगी। उन्होंने कहा

कि सरकार बनाने के लिए 21 सीटों को जरूरत है जबकि उनकी पार्टी को 25 से ज्यादा सीटें अप्राप्ति किया है। बता दें कि मिलने जा रही है। इस बार, कोरोना की चुनौती के बाद भी राज्य में विकास कार्य हुए हैं। इसलिए जनता को उनकी सरकार पर भरोसा है।

मुख्यमंत्री जारमथांग ने कहा कि राज्य में वह भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र में वह एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बहुप्रत के साथ है। लेकिन इस एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बहुप्रत के अब तक न तो भाजपा ने

गठबंधन के लिए कहा है और न है। उन्होंने ही भाजपा से कोई आग्रह किया है। बता दें कि जारमथांग ऐजल ईंटर - 1 से चनाव लड़ रहे हैं। इस बार 40 सीटों के लिए 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव परिणाम का ऐलान 3 दिसंबर को किया जाएगा। मिजानेर के अलावा राज्यसभा के अलावा भवानीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हैं कि मुझे किसी स्टेडियम की जरूरत नहीं है। ममता ने कहा कि मेरे नाम पर कोई स्टेडियम या फिर रोड नहीं है। ममता बनर्जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तंज का है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को 100 दिनों के काम के बाद भी पेमेंट नहीं मिल पा रही है। ममता ने कहा, हमें मनरेंगा के सील किया गया है।

ममता बनर्जी ने कसातंज - मैंने अपने नाम पर कोई सड़क या स्टेडियम नहीं बनवाया

कोलकाता, एजेंसी।

परिचम बंगाल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की ओर से कई स्थीरों के लिए फँड न जारी किए जाने पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने भवानीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हैं कि मुझे किसी स्टेडियम की जरूरत नहीं है। ममता ने कहा कि मेरे नाम पर कोई स्टेडियम या फिर रोड नहीं है। ममता बनर्जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने तंज का है। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को 100 दिनों के काम के बाद भी पेमेंट नहीं मिल पा रही है।

ममता ने कहा, हमें मनरेंगा के

लिए केंद्र सरकार की ओर से

फँड अटका है।



आवास और सड़क योजना के

लिए भी केंद्र सरकार की ओर से

सिख समूदाय ने अपना सर्वश्रेष्ठ

उन्होंने कहा दुर्गा पूजा के एक आयोजन में कहा कि हम सद्व्यक्त और धर्मिक एकता का समान संदर्भ दे रहे हैं। एक तरफ विभाजनकारी राजनीति नहीं घोटाले के अरोप में ज्योतिष्प्रय मलिक को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है तो वही मुहुआ मोइत्रा के खिलाफ संसदीय समिति जांच कर रही है। उन पर कैसे के बदले सबाल पूछने का आरोप लगा है। इसके अलावा ममता बनर्जी के भारीजे अधिकारी बनर्जी के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। पीएम दुनिया ही वैश्विक ग्राम है। मैं अपनी जनन्यम से आप करता हूं। इसलिए मैं ज्यादातर चुप ही रहती हूं और किसी भी नेता पर निजी हमले नहीं करती। उन्होंने कहा कि यह धरती तो रही है और उनसे प्रूछाता भी की जा चुकी है। इसके अलावा कई अन्य भी अरेस्ट हो चुके हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार के मामलों में विरी टीएमसी क्या रणनीति अपनाएगी, यह देखने वाली बात होगी।

लखनऊ की 2.6 हजार सेक्स वर्कर भी चुनौंगी सांसद, मतदाता सूची में शामिल

लखनऊ, एजेंसी लखनऊ में करीब 2.6 हजार सेक्स वर्कर हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन सेक्सरी एजेंसियों की मिट्टद से इनको चिह्नित कर मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सेक्स वर्कर भी इस बार सांसद चुनावों के लिए मताधिकारी का प्रयोग कर सकते। चुनाव आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। इनके बाद एसएम इंटर्नेशनल विशेष नियन्त्रण और समाज कल्याण विभाग के सम्मेलन में भाग लिया गया।

जलनऊ की 2.6 हजार सेक्स वर्कर भी चुनौंगी सांसद, मतदाता सूची में शामिल

लखनऊ, एजेंसी लखनऊ में करीब 2.6 हजार सेक्स वर्कर हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन सेक्सरी एजेंसियों की मिट्टद से इनको चिह्नित कर मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सेक्स वर्कर भी इस बार सांसद चुनावों के लिए मताधिकारी का प्रयोग कर सकते। चुनाव आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। इनके बाद एसएम इंटर्नेशनल विशेष नियन्त्रण और समाज कल्याण विभाग के सम्मेलन में भाग लिया गया।

जलनऊ की 2.6 हजार सेक्स वर्कर भी चुनौंगी सांसद, मतदाता सूची में शामिल

लखनऊ, एजेंसी लखनऊ में करीब 2.6 हजार सेक्स वर्कर हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन सेक्सरी एजेंसियों की मिट्टद से इनको चिह्नित कर मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सेक्स वर्कर भी इस बार सांसद चुनावों के लिए मताधिकारी का प्रयोग कर सकते। चुनाव आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। इनके बाद एसएम इंटर्नेशनल विशेष नियन्त्रण और समाज कल्याण विभाग के सम्मेलन में भाग लिया गया।

जलनऊ की 2.6 हजार सेक्स वर्कर भी चुनौंगी सांसद, मतदाता सूची में शामिल

लखनऊ, एजेंसी लखनऊ में करीब 2.6 हजार सेक्स वर्कर हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन सेक्सरी एजेंसियों की मिट्टद से इनको चिह्नित कर मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सेक्स वर्कर भी इस बार सांसद चुनावों के लिए मताधिकारी का प्रयोग कर सकते। चुनाव आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। इनके बाद एसएम इंटर्नेशनल विशेष नियन्त्रण और समाज कल्याण विभाग के सम्मेलन में भाग लिया गया।

जलनऊ की 2.6 हजार सेक्स वर्कर भी चुनौंगी सांसद, मतदाता सूची में शामिल

लखनऊ, एजेंसी लखनऊ में करीब 2.6 हजार सेक्स वर्कर हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन सेक्सरी एजेंसियों की मिट्टद से इनको चिह्नित कर मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सेक्स वर्कर भी इस बार सांसद चुनावों के लिए मताधिकारी का प्रयोग कर सकते। चुनाव आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। इनके बाद एसएम इंटर्नेशनल विशेष नियन्त्रण और समाज कल्याण विभाग के सम्मेलन में भाग लिया गया।

जलनऊ की 2.6 हजार सेक्स वर्कर भी चुनौंगी सांसद, मतदाता सूची में शामिल

लखनऊ, एजेंसी लखनऊ में करीब 2.6 हजार सेक्स वर्कर हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन सेक्सरी एजेंसियों की मिट्टद से इनको चिह्नित कर मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सेक्स वर्कर भी इस बार सांसद चुनावों के लिए मताधिकारी का प्रयोग कर सकते। चुनाव आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। इनके बाद एसएम इंटर्नेशनल विशेष नियन्त्रण और समाज कल्याण विभाग के सम्मेलन में भाग लिया गया।

जलनऊ की 2.6 हजार सेक्स वर्कर भी चुनौंगी सांसद, मतदाता सूची में शामिल

लखनऊ, एजेंसी लखनऊ में करीब 2.6 हजार सेक्स वर्कर हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन सेक्सरी एजेंसियों की मिट्टद से इनको चिह्नित कर मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सेक्स वर्कर भी इस बार सांसद चुनावों के लिए मताधिकारी का प्रयोग कर सकते। चुनाव आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। इनके बाद एसएम इंटर्नेशनल विशेष नियन्त्रण और समाज कल्याण विभाग के सम्मेलन में भाग लिया गया।

जलनऊ की 2.6 हजार सेक्स वर्कर भी चुनौंगी सांसद, मतदाता सूची में शामिल

लखनऊ, एजेंसी लखनऊ में करीब 2.6 हजार सेक्स वर्कर हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन सेक्सरी एजेंसियों की मिट्टद से इनको चिह्नित कर मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सेक्स वर्कर भी इस बार सांसद चुनावों के लिए मताधिकारी का प्रयोग कर सकते। चुनाव आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। इनके बाद एसएम इंटर्नेशनल विशेष नियन्त्रण और समाज कल्याण विभाग के सम्मेलन में भाग लिया गया।

जलनऊ की 2.6 हजार सेक्स वर्कर भी चुनौंगी सांसद, मतदाता सूची में शामिल

लखनऊ, एजेंसी लखनऊ में करीब 2.6 हजार सेक्स वर्कर हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन सेक्सरी एजेंसियों की मिट्टद से इनको चिह्नित कर मतदाता सूची में शामिल किया गया है। सेक्स वर्कर भी इस बार सांसद चुनावों के लिए मताधिकारी का प्रयोग कर सकते। चुनाव आयोग ने इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए थे। इनके बाद एसएम इंटर्नेशनल विशेष नियन्त्रण और समाज कल्याण विभाग के सम्मेलन में भाग लिया गया।

जलनऊ की 2.6 हजार सेक्स वर्कर भी चुनौंगी सांसद, मतदाता सूची में शामिल

लखनऊ, एजेंसी लखनऊ में करीब 2.6 हजार सेक्स वर्कर हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर तीन सेक्सरी एजेंस